नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों को विदेशों में भेजा जाना

2112. कुमारी आलिया : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा कुछ अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए विदेशों में भेजा गया है, यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या क्या है और जिन देशों में उनको भेजा गया है, उनके नाम क्या हैं ; और

(ख) उन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या क्या है ?

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी, हां, पिछले दो वर्षों अर्थात् 1988–89 और 1989–90 के दौरान 14 अधिकारियों (समूह "क" से 12 तथा समूह "ख" से 2) को प्रशिक्षण पर यू० के०, जापान, कनाडा, अमेरिका और स्वीडन भेजा गया था।

(ख) इन में से समूह "क" का एक अधिकारी अनुसूचित जाति का था।

Violation of Rules in granting Extension in Service in the Office of the Deve. lopmeut Commissioner (Handicrafts)

2113. SHRI SYED SIKTEY RAZI: Willi the Minister of TEXTILES be state:

(a) whether it is a fact that instructions/rules have been violated by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts) and also proper procedures were not followed in the matter of granting extension of service On attaining the age of superannuation and on completion of prescribed period of deputation; and

(b)' if so, what action is being taken to rectify matters and fix responsibility for the irregularities?

THE MINISTER OF TEXTILES WITH ADDITIONAL CHARGE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI SHARAD YADAV): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Loan Melas held by the New Government

2114. SHRI KAPIL VERMA:
KUMARI ALIA:
SHRIMATI VEENA VERMA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether any "loan melas" were held after installation of the new Government at the centre and whether the melas will be continued in the new financial year; and

(b) what is the amount distributed at the melas during the current financial year and also during the last three months and what is the allocation for next year?

THE MINISTER OF FINANCE (PROF. MADHU DANDAVATE): (a) and (b) Neither the Central Government nor the Reserve Bank of Indiax have formulated any scheme for disbursement of credit by banks through "loan melas" or Credit Camps. The public sector banks have been organising the credit camps in order to provide credit assistance to weaker sections. The data reporting system of banks does not yield any regular information in respect of such camps.

"कोसा" रेशमी धागे का उत्पादन

2115. श्री अजीत जोगी :
श्री सोहन लाल धूसिया :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में "सरई" वृक्षों पर कोसा को

प्राकृतिक रूप से उगाया जाता है और यह कि यह आदिवासियों की आजीविका का स्रोत है और उससे कोसा रेशमी धागा तैयार होता है ;

(ख) आदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस रेशमी धागे के उत्पादन से संबंधित आदिवासी पर्याप्त आय का अर्जन कर पाये हैं; क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या आदिवासी क्षेत्रों के लिए कोई योजना तैयार की जाएगी और उसे वहां कार्यान्वित किया जाएगा, ताकि रेशमी धागे का उत्पादन बढ़ सके ; और

(घ) क्या ऐसी योजना देश के किसी अन्य राज्य में भी कार्यान्वित की जा रही है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्री साथ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री शरद यादव) : (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी०एस० बी०) ने तसर रेशम कीट पालन के लिए किसानों को तसर रेशमकीट बीज को और बढ़ाने और वितरण के लिए मध्य प्रदेश में छः बेसिक सीड विस्तार तथा प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है। ये प्रशिक्षण केन्द्र उन्हें अपनी आय बढ़ाने के लिए कीट पालन उत्पादकता में सुधार के लिए तसर रेशम कीट पालन की उन्नत तकनीकों में प्रशिक्षण भी देते हैं । केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) ने तसर कीट पालन मेथा कताई की आधुनिक तकनीकों में जनजाति तसेर कीटपालकों के समक्ष प्रदर्शन और प्रशिक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश में प्रदर्शन सह प्रशिक्षण केन्द्र भी स्थापित किया है । जनजातियों को विपणन सहायता प्रदान करने और बिचौलियों द्वारा जनजातियों के शोषण को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी.एस.बी.) ने रायगढ़ में एक कच्चा माल बैंक (उप-डिपो) स्थापित किया है ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय रेशम बोर्ड (सी०एस०बी०) ने तसर रेशम के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित तसर विकास परियोजनाएं तैयार की है :—

(1) पांच वर्षों की अवधि में 21 करोड़ रुपए की लागत से उष्णकटिबंधीय तसर विकास परियोजना, जिसमें शामिल है बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक राज्य ।

(2) 4 वर्षों की अवधि में 14 करोड़ रुपए की लागत से तसर रेशमकीट बीज परियोजना जिसमें शामिल है बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, और उत्तर प्रदेश राज्य।

(3) चार वर्षों की अवधि में 5.59 करोड़ रुपए की लागत की एक अनुवर्ती चरण की अन्तरराज्यीय तसर परियोजना स्विस सहायता से उड़ीसा और महाराष्ट्र राज्यों में कार्यान्वित की जा रही है ।

गांजे और अफीम की खेती

2116. **श्री अजीत जोगी :**

श्री मोहन लाल झूलिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि संबद्ध विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से प्रतिवर्ष गांजे और अफीम की खेती हेतु भूमि के अधिकृत क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर इनकी खेती की जा रही है, जिससे इनकी तस्करी की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ; और